

किसानों को मोदी के पैसे का इंतजार

केंद्र सरकार का दावा : साढ़े 14 लाख किसानों को करोड़ों बांट दिये

मजदूर मोर्चा ब्लूरे

फरीदाबाद: मोदी सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को लागू हुए 11 महीने हो चुके हैं। अकले हरियाणा में 78040 किसानों को पैसे की पहली किश्त तक नहीं मिली है। यूपी, पंजाब और अन्य राज्य के किसानों की संख्या तो हरियाणा से भी ज्यादा है। हरियाणा में किसान पहली किश्त पाने के लिए दर्द-दर्द भटक रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने इससे संबंधित फॉर्मों पर आधार और खाता नंबर तक भर दिए हैं लेकिन उन्हें इस केंद्रीय योजना का एक पैसा भी नहीं मिला है।

अगर आप इस योजना से संबंधित भारत सरकार के पोर्टल पर नजर डालेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि हरियाणा के 15,22,677 किसान लाभार्थियों में से 14,44,637 किसानों को 30 जनवरी 2020 तक पहली किश्त का पैसा दिया जा चुका है। भारत सरकार के इसी पोर्टल पर लिखा है कि 14,13,152 किसानों को दूसरी किश्त, 13,35,144 किसानों को तीसरी किश्त और 8,68,308 किसानों को इस योजना की चौथी किश्त का भी पैसा दे दिया गया है।

हरियाणा की हकीकत क्या है

हरियाणा के जमीनी हालात भारत सरकार की इस योजना की पोल खोलने के लिए काफी हैं। हरियाणा के इन जिलों में अभी पहली किश्त का ही पैसा किसानों को नहीं मिला है। इनमें रोहतक में 12,273 किसान, भिवानी में 12,114 किसान, जींद में 6783 किसान, कुरुक्षेत्र में 5866 किसान, रेवाड़ी में 5421 किसान, सोनीपत में 5372 किसान, मेवात में 4725 किसान, झज्जर में 4573 किसान, करनाल में 3741 किसान, फतेहाबाद में 3495 किसान, चरखीदादरी में 2966 किसान, महेंद्रगढ़ में 2873 किसान, यमुनानगर में 2555 किसान, पानीपत में



किसानों को मोदी का 'अनमोल' तोहफा 'किसान रेल'

गरीबी व कर्जों के बोझ तले दम तोड़ते किसानों को मोदी सरकार ने आज (पहली फ़रवरी) अपने बजट में एक बेहद 'अनमोल' तोहफ़ा देने की घोषणा की है। यह तोहफ़ा अनमोल इसलिये है कि इस पर न तो सरकार का कोई पैसा खर्च होने वाला है और न ही किसी किसान को एक पैसे का लाभ होना है। यह तोहफ़ा है कि किसान रेल। इसमें सरकार ने कुछ नहीं करना, बस किसी एक ट्रेन का नाम 'किसान रेल' रख दिया जायेगा।

वह बात अलग है कि उस ट्रेन में न तो किसी किसान को नौकरी मिलेगी, न ही कोई काम-धंधा और न ही यात्रा करने में किसी प्रकार की कोई रियायत। अन्य सभी यात्रियों की तरह किसान को भी ब्लैक में टिकट खरीद कर ही 'अपनी' इस ट्रेन में चढ़ पायेगा।

महम (ज़िला रोहतक) के 80 वर्षीय किसान महेंदर सिंह से जब इस किसान रेल पर टिप्पणी मांगी तो उन्होंने कहा कि वे बीते एक साल से अपनी 'किसान पैसेन' के लिये महम से रोहतक के बीच धक्के खा रहे हैं, सेंकड़ों रुपये का भाड़ा खर्च करके एक पैसा नहीं मिला। यह रेल भी ऐसा ही ढकोसला है।

1897 किसान, सिरसा में 1639 किसान, पलवल में 1389 किसान, युग्मांव में 450 किसान, कैथल में 384 किसान, फरीदाबाद में 343 किसान, अंबाला में 341 किसान और पंचकूला जिले में 132 किसानों को

इस केंद्रीय योजना की एक दमड़ी भी पहली किश्त में नहीं मिली है।

दो साल हो गए योजना शुरू हुए

यह योजना प्रधानमंत्री मोदी ने 1 दिसंबर 2018 में शुरू की थी। एक साल का समय था कि किसान इस दौरान अपना फॉर्म भर लें और दस्तावेज जमा करा दें, ताकि उन्हें इस योजना का लाभ 1 फरवरी 2019 से मिल सके। आज टीक 1 फरवरी 2020 है और किसानों के खाते में एक नया पैसा नहीं आया है। जब योजना शुरू की गई थी तो छोटे किसानों और किसान मजदूरों को किसानों को आर्थिक सहायता के तौर पर 6 हजार रुपये देने की घोषणा की गई थी।

केहर सिंह नामक किसान ने कहा कि मैंने पिछले साल इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराया था लेकिन अब तक एक पैसा भी मेरे बैंक खाते में नहीं आया। भारतीय किसान यूनियन हरियाणा ब्रांच के पूर्व अध्यक्ष सेवा सिंह आर्थ की मांग है कि सरकार हरियाणा में कम से कम पहली किश्त का पैसा तो जारी करे। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने के बाद आधार नंबर न बताने वाले किसानों का उत्पीड़न किया गया। सरकार को चाहिए अपने डेटा को ठीक करे और किसानों का उत्पीड़न बंद किया जाए।

हरियाणा कृषि विभाग के संयुक्त सचिव जगराज डांडी ने कहा कि लाभार्थियों को पहली किस्त बांटने की प्रक्रिया चल रही है।

लाभार्थियों का वेरिफिकेशन हो चुका है और डेटा अपडेट कर दिया गया है। पहले आधार नंबर इस योजना में जरूरी नहीं था लेकिन बाद में इसकी जरूरत पड़ी और डेटा फिर से अपडेट किया गया।

आखिर पैसा कहां जा रहा है

योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2018 में यूपी के गोरखपुर से की थी। इस स्कीम के तहत साल भर में 87 हजार करोड़ रुपये किसानों के बैंक खाते में डाले जाने थे, जिसमें से अब तक करीब 30 हजार करोड़ खर्च हुए हैं। तीसरी किश्त सिर्फ 3.74 करोड़ लोगों को ही मिल सकी है। इसी तरह दूसरी किश्त लेने वाले किसानों की संख्या करीब 6.25 करोड़ है जबकि देश में 14.5 करोड़ किसान परिवार हैं। आधार वेरीफिकेशन में देरी की वजह से तीसरी और अंतिम किश्त का पैसा पहुंचने में देर हो रही है। लेकिन भारत सरकार के दावों के विपरीत किसी भी राज्य में इस पैसे बांटे जाने को लेकर कोई पारदर्शिता नहीं है।

अन्य राज्यों का हाल भी जानें

केंद्रीय कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक भाजपा शासित कर्नाटक में 7,55,026 किसानों को पैसा मिल चुका है। पंजाब के 13,35,601 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। हालांकि कांग्रेस शासित मध्य प्रदेश में काफी कम रकम पहुंची है। 24 जन तक की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सिर्फ 12,888

किसानों को फायदा मिला है। बिहार के 7,82,885, छत्तीसगढ़ के 4,36,119, और उत्तराखण्ड के 4,29,082 किसानों को लाभ मिला है। दूसरी किस्त करीब तीन करोड़ किसानों को मिल चुकी है। हालांकि कृषि मंत्रालय के कई सूची ने इस बात पर शक जताया है कि हरियाणा के मुकाबले बिहार जैसे बड़े राज्य में करीब आठ लाख किसानों को इतनी जल्दी पैसा बांटा जाना नामुमकिन है क्योंकि वहां आज भी आधुनिक बैंकिंग सिस्टम में तमाम खामिया हैं।

छोटे किसानों के लिए शुरू की गई योजना में कई खामियां भी हैं, इसके अलावा योजना के लाभ के लिये आधार को बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य किया गया है। संभवतः इसके कारण कई छोटे एवं सीमांत किसान योजना से बाहर हुए हैं। इसके कारण उत्तर प्रदेश में 1.4 करोड़ तथा पूरे देश में 5.8 करोड़ किसानों को चौथी किस्त नहीं मिलने की आशंका है।

इस बारे में बेंगलुरु स्थित इंस्टीट्यूट फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज के प्रोफेसर और अर्थशास्त्री डॉ. प्रमोद कुमार ने कहा, छोटे किसानों की आय बढ़ाने के इरादे से यह योजना लाइंग गई लेकिन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लाभार्थियों की सूची लगातार घट रही है। यह बताता है कि बड़ी संख्या में किसान इस योजना से बाहर हो रहे हैं। पोर्टल पर डाले गये आंकड़ों में विसंगतियां पायी गयी हैं। इसके अलावा योजना के लाभ के लिए आधार को बैंक खाते से जुड़ा होना अनिवार्य किया गया है। शायद इसी कारण कई छोटे एवं सीमांत किसान योजना से बाहर हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसके कारण उत्तर प्रदेश में 1.4 करोड़ तथा पूरे देश में 5.8 करोड़ किसानों को चौथी किस्त नहीं मिलने की आशंका है।

कहां करें शिकायत

सोमवार से शुक्रवार तक पीएम-किसान हेल्प डेस्क के ई-मेल pmkisan-ict@gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी न बात बने तो इस सेल के फोन नंबर 011-23381092-डायरेक्ट हैल्पलाइन पर फोन करें।



घर बैठे प्राप्त करें मजदूर मोर्चा

आज ही अपने हाँकर से कहें, कोई दिक्कत हो तो शर्मा न्यूज एंजेंसी से फोन नं 9811159238 पर बात करें। बल्भगढ़ के पाठक अरोड़ा न्यूज एंजेंसी से 9811477204 पर बात करें।

अन्य बिक्री केन्द्र :

- आनंद मैगजीन सेंटर केसी रोड, एनएच-5
- प्रिंट फोर्ट, टेलीफोन एक्सचेंज के सामने नेहरू ग्राउंड
- रेलवे बुक स्टाल ओल्ड रेलवे स्टेशन
- एनआईटी रेलवे स्टेशन के बाहर बाटा चौक पुल के नीचे
- राम खिलावन बल्भगढ़ बस अड्डा पुलिस चौकी के सामने
- हितेश ग्रोवर सैक्टर 29 पेट्रोल पम्प के पास
- जितेन्द्र, बाटा सेंटर - 9971064207

घर में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने 9 और महिला कॉलेज, सिर्फ घोषणाओं में

अभी पीछे है।

इनमें से सिर्फ ब